प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
05.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

''आज के मुख्य समाचार''

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में देशभर के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा–इस वर्ष पहली मार्च के बाद प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में मोबाईल फोन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल को आरडीजी बंद होने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार को ठहराया जिम्मेवार।
- स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा– लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
- प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आगामी 3 मार्च से होंगी शुरू।

प्रधानमंत्री–परीक्षा पे चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 6 फरवरी को सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में देशभर के विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा के तनाव पर चर्चा करना और परीक्षाओं को एक उत्सव व जीवन के एक ज़रूरी हिस्से के तौर पर मनाना है। इस साल परस्पर संवादात्मक सत्र देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर, गुवाहाटी और दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एग्जाम वॉरियर्स के साथ होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि माईगॉव पोर्टल के ज़रिए इस कार्यक्रम के लिए चार करोड़ पचास लाख से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। यह कार्यक्रम दूरदर्शन, प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसे वेव्स ओटीटी, अमेजॉन प्राइम वीडियो, जियो, जी–5, सोनी लिव और स्पॉटीफाइ सहित कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सजीव प्रसारित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री

प्रदेश सरकार इस वर्ष एक मार्च के बाद राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में मोबाइल फोन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएगी और स्कूल परिसर में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आयोजित नेशनल हैंडबाल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी के पास मोबाईल पाया गया तो उस पर 5 सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, मोबाइल जब्त किया जाएगा और उसके माता–पिता को स्कूल बुलाकर समझाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बार–बार नियम तोड़ने पर तय एसओपी के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग जल्द ही मानक प्रक्रिया तैयार करेगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने झण्डूता विधानसभा क्षेत्र के बरठीं में 42 करोड़ 43 लाख रुपये की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व

शिलान्यास भी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक पिछले 73 वर्षों से हिमाचल को ग्रांट मिल रही थी लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हिमाचल के अधिकारों के लिए भाजपा के विधायकों के नेतृत्व में दिल्ली जाने को तैयार हैं।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल के लिए राजस्व घाटा अनुदान आरडीजी बंद होने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 16वें वित्तायोग के सामने राज्य का पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। यही कारण था कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सहित 17 राज्यों को दी जाने वाली आरडीजी बंद कर दी। उन्होंने दावा किया कि 15वें वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के बारे में स्पष्ट संकेत दिए थे और हिमाचल की सुक्खू सरकार को सत्ता संभालने के बाद इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए थी लेकिन सरकार अंत तक सोई रही।

15जी फाइनेंस कमीशन ने लगभग लगभग अपना माइंड दे दिया था सभी देश के राज्यों को कि रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट आने वाले समय में हमेशा के लिए दिया जाएगा, यह जरूरी नहीं है लेकिन यह हिमाचल के ही संदर्भ में फैसला नहीं लिया गया है, अगर रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट का फैसला फाइनेंस कमीशन ने लिया है तो पूरे देश के 17 राज्यों को जिनको रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट मिलती थी ये सबके बारे में फैसला लिया। एप्रेशन पैदा होता है कि 16जी फाइनेंस कमीशन के सामने आपने अपनी बात को प्रभावी ढंग से क्यों नहीं रखा?

नेता प्रतिपक्ष ने वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट को आत्मनिर्भर भारत का आभार स्तंभ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए कर हस्तातंरण के रूप में 13 हजार 9 सौ 49 करोड़ और अनुदान सहायता के तहत दस हजार दो सौ 43 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय करों में तो हिस्सेदारी जो टैक्स डेवोल्यूशन का अनुपात 0.82 से बढ़ा करके 0.91 कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश को लगभग 11561 करोड़ रुपए पीछे जो प्राप्त हुए थे और 2026द्27 में बढ़कर के 13950 करोड रुपए मिलेगा जिसमें जो इनक्रीज है 2390 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि इस में रिफ्लेक्ट होती है जो हिमाचल के लिए अच्छी बात है।

धनीराम शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बना रही है ताकि लोगों को घरद्वार के समीप गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सके। उन्होने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। शांडिल ने कहा कि प्रदेश में पहली बार रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है और करीब एक हजार एक सौ 10 करोड़ रूपए खर्च कर स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

बोर्ड परीक्षा

राज्य में आगामी 3 मार्च से आरंभ होने वाली प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में इस बार करीब एक लाख 84 हजार विद्यार्थी भाग लेंगे। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि वार्षिक परीक्षाओं से पहले 20 से 28 फरवरी तक प्रेक्टिकल परीक्षाओं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से 2 हजार 3 सौ 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विशाल शर्मा ने बताया कि नकल रोकने के लिए फलाइंग स्क्वायड बनाए जाएंगे और साथ ही लाईव मॉनिटरिंग सैंटर भी स्थापित किया जाएगा।

हमने 2384 जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए हैं पूरे प्रदेश भर में, नकल रोकने के लिए जैसे हर बार हम फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाते हैं वो फ्लाइंग स्कोट्स लगेंगे और एक हम लाइफ मॉनिटरिंग सेंटर जो है वो बोर्ड के स्तर पर बनाएंगे ।
इस बार थोड़ा सा हम इसको बड़े स्तर पे करेंगे पहले के मुकाबले । हमारे 100% जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी है बिल्कुल ।

''अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 9वें संस्करण में देशभर के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा–इस वर्ष पहली मार्च के बाद प्रदेश के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में मोबाईल फोन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध।
- नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल को आरडीजी बंद होने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार को ठहराया जिम्मेवार।
- स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा– लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
- प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आगामी 3 मार्च से होंगी शुरू।